eradicated? Poverty is there due to over-population. So, I would like to know whether the population problem and population explosion as a threat to civilisation was discussed or not. If it was discussed, then what were the views of the other SAARC countries which were present there? We do not believe in limiting the family size. I don't think they have accepted these. I would like to know whether our family welfare proposal for tackling the population problem was there or not. This is the only clarification that I want to seek from the hon. Minister.

श्री संघ प्रिय गौतम: उपसभाध्यक्ष महोदया, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से महिलाएं किस तरह मजबूत हों यह तो ठीक है लेकिन कमला सिन्हा जी कह रही थी कि राजनीतिक दृष्टि से भी मजबूत होनी चाहिए। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे सार्क देशों में तीन देशों की हैड महिला है। बंगलादेश की प्रधान मंत्री महिला है, पाकिस्तान की प्रधान मंत्री महिला है और श्रीलंका की राष्ट्रपति महिला हैं। हमारे देश की बड़ी मजबूत प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी रही है। इजरायल में भी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से तो मजबूत है और होनी चाहिए लेकिन आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी मजबूत हो इसके लिए दो बातें इसमें बिल्कुल नजरअंदाज की गई हैं।

श्रीमती कमला सिन्हा: महिला प्रधानमंत्री के होने से महिलाएं सशक्त नहीं होती हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम: नहीं होती है तो उनका कसूर है।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): गौतम जी, आप जरा एक मिनट के लिए बैठ जाएंगे। मैंने यह आपसे इसलिए कहा कि Shri Manmohan Singhji would like to lay papers relating to Supplementary Demands for Grants (General), 1995-96 (August, 1995).

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1995-96 (AUGUST, 1995)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MANMOHAN SINGH): Madam, I beg to lay on the Table of the House a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (General) for the year 1995-96 (August, 1995).

CLARIFICATIONS ON STATEMENT BY MINISTER

SAARC Ministerial Meeting on Women Held at Dhaka on 29-30 July, 1995 (Contd.)

श्री संघ प्रिय गौतम: उपसभाध्यक्ष महोदया, बच्चों की परवरिश की सारी जिम्मेदारी महिलाओं की होती हैं। अगर उसका बच्चा बीमार हो जाए या मर जाए या उसको तलाक दे दिया जाए तो उसकी क्या हालत होगी। वह आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर रहेगी। इसलिए बच्चे कम से कम होने चाहिए। लेकिन इसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है, इस विषय को इसमें नहीं लाया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा अगर किसी महिला को तलाक दे दिया जाए तो वहा कहां जाएगी? वह चाहे किसी धर्म की हो, किसी जाति की महिला हो, तलाक के बाद उसके खर्चाखानगी की जिम्मेदारी चाहे उसके पति पर हो, चाहे उसके परिवार पर हो और चाहे समाज पर हो लेकिन इसकी किसी न किसी पर मुकर्रर करना चाहिए। वरना इसका ....(व्यवधान)...आप जिस दृष्टि से सोचते हैं उस दृष्टि से हम नहीं सोचते। आपका दृष्टिकोण अलग है। मैं मानवीय दृष्टिकोण से सोचता हूं। यह मजहब, धर्म आदमी का बनाया हुआ है। यह अल्लाह या खुदा का बनाया हुआ नहीं है। जातियां आदमियों ने बनायीं हैं, ईश्वर या खुदा ने ये जातियां नहीं बनाई हैं। नियम हमने बनाए हैं। नियम अल्ला मियां के बनाए हुए नहीं हैं। नियम बदल सकते हैं, नियमों में संशोधन हो सकता है।

तलाक के बाद महिलाओं के खर्चा खानगी की जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। तीसरी बात मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गयी। एक बारात में सब जवान ही जवान चले गए। शादी बड़ी मुश्किल से हुई। उन्होंने लड़की वालों को कहा कि हम लोग बकरे खायेंगे हम 50 आदमी हैं। उन्होंने कहा कि आपको 50 बकरे एक साथ खाने पड़ेंगे। अब उनको परेशानी यह हुई कि हम 50 बकरे कैसे खायें। वे चोरी से एक बुड्ढे को ले आये। उस बड्ढे ने कहा कि एक-एक को काटो, भूनो और एक-एक बोटी खाओ। तो हमने यह माना कि वह महिलाओं का सम्मेलन है लेकिन इसमें एक-दो पुरूष भी जाने चाहिए थे।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आपको भेजने की सिफारिश कर दें।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, बीजिंग में होने वाली चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन की तैयारी के लिए ढाका में सार्क देशों का जो सम्मेलन हुआ है, उसके संबंध में जो वक्तव्य मंत्री महोदया ने पेश किया है, मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। साथ ही में उनको इस बात के लिए भी धन्यवाद देती हूं कि हमारे पास एक पत्र आया है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल में जो मौजूदा महिला सांसद हैं, वे सभी वहां जा सकेंगी। लेकिन इन सांसदों की क्या भूमिका होगी, इस विषय में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जहां तक हमें जानकारी मिली है, जो पत्र हमें प्राप्त हुआ है उसमें यह कहा गया है कि एक सांसद के रूप में हमारी कोई भूमिका नहीं होगी। तो मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगी कि इस विश्व सम्मेलन में एक सांसद के नाते, प्रतिनिधिमंडल में जो सांसद होगी, उनकी क्या भूमिका होगी? इसके अलावा मैं मंत्री महोदया के इस वक्तव्य से उत्पन्न कुछ सवालात उनसे कहना चाहूंगी।

महोदया, मंत्री महोदया ने कहा है कि इस मंत्रिस्तरीय बैठक में हमने नौरोबी में जो फारवर्ड लुकिंग स्ट्रैटजी तैयार की है, जिसमें करीब 350 पैराग्राफ हैं, उसकी हमने समीक्षा की है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि वह समीक्षा आपकी क्या है और इस समीक्षा में सार्क देशों और विशेषकर भारत की क्या भूमिका रही है?

फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों पर एक विशद् विवेचन किया गया और उन तमाम दृष्टियों की रोशनी में मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगी कि भारत सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं? फारवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी में जिस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित किया गया वह था आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की बराबर की भागीदारी और आर्थिक रूप में महिलाओं पर किस-किस तरह के अत्याचार होते हैं, किस-किस तरह के भेदभाव होते हैं और किस-किस तरह से महिलाओं के शोषण होते हैं। इन तमाम पक्षों को बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया गया था और इसी में यह भी कहा गया था कि टेक्नोलोजी और तकनीकी, मार्किट इकोनामी, बाजार अर्थ व्यवस्था का महिलाओं पर किस तरह प्रभाव पड़ता है। भारत हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चार कदम सूरज की ओर जब बढ़ा रहा है, यह चार कदम सूरज की ओर बढ़ रहे हैं तो इसमें महिलाओं ने कितने कदम आगे बढ़ाए? हमारे देश की मार्किट इकोनोमी में हमारे देश की महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जहां तक मुझे जानकारी है हमारे देश के लिए जो कंट्री पेपर तैयार किया गया था, उस में भी इस बात का उल्लेख है कि बाजार अर्थ व्यवस्था का हमारे देश की महिलाओं पर खास कर के कामगार महिलाओं पर, घरेलु दस्तकारी का काम करने वाली महिलाओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और इन कामों में उसकी भागीदारी कम होती जा रही है। भयंकर शोषण का शिकार होती जा रही है। काम के अवसर उनके लिए कम होते जा रहे हैं और जिन-जिन देशों में मार्किट इकोनोमी का प्रयोग किया जा रहा है उन देशों में देखा जा रहा है कि हमारी महिलाएं जिनको काम से वंचित होना पड़ रहा है वे महिलाएं दूसरे-दूसरे यानी जो काम उनकी गरिमा को कम करते हैं, ऐसे धंधों में उन्हें जाना पड़ रहा है।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप थोड़ा कम बोलिये। आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: मैं यह कहना चाहती थी कि जिन-जिन देशों में यह प्रयोग हो रहे हैं, वहां-वहां महिलाएं वैश्यावृत्ति की ओर अग्रसर हो रही हैं। कंट्री पेपर में भी इसका उल्लेख किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी दो दिन पहले हमारी अखबारों में रिपोर्ट आई है कि आसाम से पांच हजार महिलाओं को सिंगापुर भेजा जा रहा है। यह सवाल उठाये गये कि यह पांच हजार महिलाएं जो सिंगापुर जा रही हैं, उनका इस्तेमाल गलत तरीकों में होगा, शारीरिक शोषण होगा। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगी कि नेपाल, बंगलादेश, भारत, सार्क के जो देश हैं, इन देशों में जो ब्यूमेन ट्रेफिकिंग बढ़ता जा रहा है, क्या इस विषय पर बातचीत की गई और मार्किट इकोनोमी का इन देशों की अर्थव्यवस्था पर और इस अर्थ व्यवस्था का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इस पर विशद् विवेचन नहीं किया गया? अगर विशद् विवेचन किया गया तो उस विवेचन के क्या निष्कर्ष उभर कर आए, क्या आप वह हमारे सामने रखेंगे?

SHRI ASHOK MITRA : (West Bengal) : Can I intervene for a moment? On this issue I had raised a question in the previous Session of our House and I did draw the attention of the House to a report that 75,000 women from our country were being planned to be sent out to Singapore to work as maids. God

alone knows whether they will work as maids or they will disappear in the flesh markets of South East Asia. I wish there is some response from the Government's side. The Minister of State for Parliamentary Affairs was present on that day and promised us some information on that but till now nothing has been told to us.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : धन्यवाद। आदरणीय अशोक मित्रा जी ने जो कहा, मैंने भी उनका समर्थन किया था और इस मुद्दे को उठाया था। बहरहाल, मंत्री महोदया, इस संदर्भ में इन देशों की स्थिति को स्पष्ट करेंगी और विशेषकर भारत की स्थिति को स्पष्ट करेंगी क्योंकि भारत सरकार की एक्सपोर्ट प्रोमोशन कोसिल महिलाओं का निर्यात कर रही है दूसरे बाज़ारों में। यह हमारे लिए चिंता और शर्म की बात है। इसी वक्तव्य के संदर्भ में मेरा मंत्री महोदया से दूसरा सवाल है जिसमें कहा गया था दक्षेस कार्यवाही योजना पर विचार किया गया। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगी कि इस दक्षेस कार्यवाही योजना के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य क्या थे। और इस दक्षेस की जो कार्यवाही योजना थी एक्शन प्लान इसमें भारत सरकार की प्रगति के आंकड़े क्या हैं— ताजा आंकड़े। इनको मंत्री महोदया सदन को अवगत कराएंगी तो अच्छा रहेगा। इसी वक्तव्य में कहा गया है कि "विकास में महिलाएं" विषय पर" आयोजित मंत्रि स्तरीय दो बैठकें की गयीं। मैं यह जानना चाहूंगी कि "विकास में महिलाएं" इस विषय पर जब आपने दो दो बैठके की तो इन बैठकों की मुख्य अनुशंसाएं क्या थीं, क्या रिकमेंडेशंस थीं, क्या सिफारिशें थीं और इन पर क्या-क्या निष्कर्ष उभरकर आए और भावी योजनाएं क्या तय की गयीं।

उपसभाध्यक्ष महोदया, नैरोबी फारवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी में यह बात कही थी कि तमाम देश अपने अपने देशों कानूनों की समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि उन कानूनी में कौन सी त्रुटियां हैं जो महिलाओं को समाज में हर क्षेत्र में समान भागीदारी से बाधित करती हैं। मेरा मंत्री महोदया से यह कहना है कि इस दिशा में हमारी भारत सरकार ने क्या क्या प्रयत्न किए हैं? क्या हमारे देश की सरकार ने कानूनों की समीक्षा के लिए कोई कमेटी बनायी है? इसी संदर्भ में मेरा मंत्री महोदया से सवाल है कि ये जो सार्क देश हैं जिनकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अभिरुचियां प्रायः एक सी है कुछ विभिन्नताएं अवश्य हैं, इनमें एक समानता हम देखते हैं कि खास करके इन देशों में हाल ही में पुरातनपंथी विचारधाराओं का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये पुरातनपंथी विचारधाराएं, ये रिट्रोग्रेसिव आइडियाज सामाजिक स्तर पर महिलाओं की प्रगति को बाधित कर रहे हैं। जान एफ फर्नेन्डीज ने अभी हाल ही में बंगलादेश की घटना का उल्लेख किया है। बहुत ही शर्मनाक घटना है और हमारे देश में भी हम देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं अपवाद नहीं हैं। हमारे देश में भी इस तरह की शक्तियां उभर रही हैं और इस तरह की शक्तियों के उभरने से महिलाओं की प्रगति में बाधा निश्चित रूप से स्वाभाविक ही हैं क्योंकि ये जो तमाम रिट्रोग्रेसिव आइडियाज हैं, पुरातनपंथी विचारधाराएं हैं यह महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक प्रगति में मुख्य रूप से बाधक हैं। इन पुरातनपंथी शक्तियों के उभरने के क्या कारण हैं? इन पुरातनपंथी शक्तियों और विचारधाराओं का मुकाबला किस तरह से किया जाए इस दिशा में क्या कोई विचार विमर्श वहां पर हुआ? अगर हुआ तो इसका निष्कर्ष क्या है।

इसके अतिरिक्त मैं अभी "वीमेन एण्ड मेन इन इंडिया, 1995" पुस्तक को उलट पलट कर देख रही थी। इसमें जो आंकड़े हैं वे बहुत ही चौकाने वाले हैं। राजनीतिक में महिलाओं की भागीदारी कम होती जा रही है और महिलाओं की राजनीति में भागीदारी कम होने का कारण हम सभी जानते हैं कि जहां यह महिलाओं में आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कमजोरी है वहीं पर राजनीति का अपराधीकरण जिस तरह से बढ़ता जा रहा है वह भी महिलाओं की भागीदारी कम होने का एक कारण है। इसमें आंकड़े दिए गए हैं। आपको आश्चर्य होगा कि किस तरह हमारे पहले चुनाव से लेकर 10वें चुनाव में प्रतिशत में लगातार कटौती हो रही है। इसी तरह से महिला मंत्रियों का प्रतिशत भी बहुत प्रशंसनीय नहीं है। सिर्फ एक कैबिनेट स्तर की महिला मंत्री है। मेरा यह कहना है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आपने क्या कोई कदम उठाए हैं? यह जो इम्पावरमेंट आफ वीमेन है, महिलाओं को किस तरह से शक्तिशाली बनाया जाए, निर्णायक निकायों में महिलाओं को किस तरह से उच्च स्थान दिए जाएं, इसके लिए आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं? दक्षेस सम्मेलन में यह बात कही गयी थी कि एक राष्ट्रीय मशीनरी, नेशनल मशीनरी हम बनाएंगे। मैं यह जानना चाहती हूं कि यह जो नेशनल मशीनरी पर आप लोगों ने अपना संकल्प लिया इस नेशनल मशीनरी, राष्ट्रीय मशीनरी का पूरा प्रारूप क्या है? इसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? कौन कौन से क्षेत्र आपने निर्धारित किए हैं ताकि महिलाएं आपके इस ढांचे का इस्तेमाल करके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और

राजनीतिक क्षेत्र में बराबर की भागीदारी निभा सकें। बराबर की भागीदारी की भूमिका अदा कर सकें, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी? उपाध्यक्ष महोदया, इन तमाम प्रश्नों की रोशनी मे मैं यह भी कहना चाहूंगी कि "नैरोबी फारवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी" इतनी विशद् है, इतनी व्यापक है, सांस्कृतिक प्रदूषण की हाल ही में चर्चा की गयी है और हम बीजिंग में जा रहे हैं और बीजिंग की सरकार ने अभी कुछ दिन पहले साम्राज्यवादियों की एक कंपनी को बीजिंग से धकेल बाहर कर दिया था क्योंकि वे वहां सांस्कृतिक हमला कर रहे थे, वहां सांस्कृतिक प्रदूषण फैला रहे थे। तो जब आकाश इतना छोटा हो गया है, जब राष्ट्रीय सीमाएं-सीमाएं नही रही है, इस दिशा में आज जो संस्कृति को इतना बड़ा खतरा है, संस्कृति पर साम्राज्यवादियों द्वारा हमले हो रहे हैं तो उस हमले की ओर क्या इस "दक्षेस" में चर्चा की गयी क्योंकि यह खासकर हमारे जैसे विकासशील देशों और भारत जैसे देशों के लिए खतरा है जिनका कि बहुत बड़ा सांस्कृतिक गौरव रहा है? उपसभाध्यक्ष महोदया, यह आश्चर्य की बात होगी कि आज हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं और जो इंटरलैक्चुअल्स हैं जोकि इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे देश की संस्कृति जोकि हजारों वर्षों की संस्कृति है, जिसे कि अंग्रेज नहीं मिटा पाए, जिसको "शक" नहीं मिटा पाए, "हूण" नहीं मिटा पाए, कोई नहीं मिटा पाया, क्या यह तकनीकी क्रांति इस देश की संस्कृति को पलभर में खत्म कर देगी? उपासभाध्यक्ष महोदया, ऐसा हो रहा है।

इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगी कि इस प्रश्न को गौण न समझते हुए आप ने इस पर महत्व देकर विचार किया है? अगर विचार किया है तो इस की क्या भावी योजनाएं तय की गयी है? धन्यवाद।

DR. BIIPLAB DASGUPTA (West Bengal) : Madam, while I agree with all the seven points which are there in the Dhaka Resolution, I find two major omissions and I would like the Minister to clarify as to why those points were not there and whether our Government is going to propose this addition of such points in the future congregations on the issues of women? The crux of the point is there in the second one. The second area of concern is the mainstreaming and empowerment of women, including involvement of women in the decision making process. How is it possible in a society where the semi-fuedal land relations have a big sway on a large number of people? How can we achieve this without land reforms? This is something which I want to raise. If you look at the different States—rank them in terms of various indicators like gender ratio, the proportion of women in the population, the literacy rate and so on, including the atrocities on women, molestation of women, rape of women, murder of women, bride-buring, eve-teasing you will find—I am not going to name the States--there are States which are very high on the list and these are also the States which are very low on the implementation of land reforms. There is a very high correlation between the very low status of women in a State and a very low level of performance as far as land reform is concerned. You will also see that these are exactly the same States where there are also the highest number of artocities against the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. What I am saying is this: While many of the demands which are there are absolutely legitimate, you cannot bring about any change to transform the society where women are treated as chatttels women are treated as if they have no sense, they have no brains, they have nothing. There the agricultural labourers, there women, their wives are treated as chattels totally under the control of the zamindars, who actually see them as part of their property and can use them in whatever way they like. The point I am saying is this. How can we omit land reforms, the need to change the feudal land relations in a large stretch of our country and still expecting to achieve equal status for women, empowerment of women, that is something which is beyond my reasoning.

I would urge very strongly on the need for land reforms in order really to achieve what you have put there on the Agenda.

The second point I would like to make this point has already been made — is on the question of value-system, the market-related kind of development and what kind of attitude they develop in regard to women. Here, Madam, we have a very serious problem. Today, if you look at the television, if you look at they way women are projected in the Bombay films, if you look at the way women are projected in all kinds of media, you get the impression as if women are an item of consumption. It is a consumer society where women are seen as an item of consumption, as a commodity. Unless we discourage this, the problem would become more serious. This can be done. This should be done by the SAARC countries themselves. All the countries who are involved in this should ensure this. They should discipline their media in such a way that this sort of projection of women is not permitted.

Madam, I would like to give an example here. I am sorry to give this example. Last year, two of our young ladies were declared as the most beautiful women of the world. One became the Miss World and the other became the Miss Universe. Then, a few months ago, there was another 'Miss World' programme in Africa where an Indian lady stood second. She did not come first; she stood second. Many people in india are very happy about it. I have nothing against these two young ladies; nothing against them. But I would like to ask this question. What is the objective of this 'Miss World' and 'Miss Universe' competitions? The women who are participating in this are under a contract with the companies concerned to work for them for one year. They appear in the advertisements made by these various organisations, these multinational companies. They appear in the advertisements for various products-from soap to perfumes and even razorblade, I think. They appear in the advertisements to promote every kind of product, not only those meant for women, but even those which are meant for men. They are under a contract for one year for the purpose of advertising the products manufactured by these multinationals. It is not a coincidence that within one year, two Indian women were selected as the 'Miss World' and the 'Miss Universe'. This is not an objective analysis. It is not an objective test which is under taken.

The point is, the West is, naturally, interested in capturing the Asian market and these sorts of competitions are linked up with that objective. This year, an African woman was selected because the competition was being held in Africa. That is also a significant point. Therefore, this is more from the consumeristic point of view. I would like to point out, in this connection, that feminist women in Europe have boycotted this kind of programme. No country in Europe has allowed this to be televised. The companies which organise these shows — everyone knows — do not make their decision based on any objective test of beauty.

In many cases, the outcomes are predetermined in order to achieve some marketing ends.

What I am saying is this, Madam. Not only we should pursue the issues which are there on the Agenda. But we should also be very careful about the way in which the market economy of the West is spreading its wings, its tentacles. They are trying to, sort of, not only make us buy their goods, but they are also making us adopt their value-system in regard to women where they are treated as an item of consumption.

Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether these two issues have been discussed. One is, the need for land reforms. Secondly, the need to discipline this consumer society so that women are not treated in this vulgar fashion. The question is whether there can be any way to stop them from doing this. These are the two specific

questions I would like to put to the hon. Minister.

Thank you.

SHRI MISA R. GANESAN (Tamil Nadu): Madam, Vice-Chairman, I would like to seek just one clarification.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): All right; only one clarification, please.

SHRI MISA R. GANESAN: Madam Vice-Chairman, it has been mentioned in this statement that the Dhaka Resolution on Women has emphasised seven areas of concern common to the SAARC countries. One of them is: 'Measures for tackling incidence of violence against women and girl child'. In this connection, I would like to seek a clarfication from the hon. Minister. In India, in the name of God, the so-called Godmen are spoiling our women. Rapes are being committed. It is only in India that this strange phenomenon is there. They say they are Godmen. They are actually goondas and rowdies. The innocent women are going to these people in the hope of getting something, but these so-called Godmen are spoiling our women. Recently, in Tamil Nadu, Madam...

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): What is your clarification?

SHRI MISA R. GANESAN: I would like to know whether any specific thing had been discussed in the Dhaka Conference in regard to women who are put to a lot of harassment by these so-called Godmen in India.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD) (SHRIMATI BASAVA RAJESHWARI): Madam Vice-Chairperson, I thank the hon. Members for having given me constructive suggestions. Many Members have participated in this discussion.

SAARC countries consist of one-fifth of the world's women population. We would like to have a common position at Beijing for the SAARC countries. We first had discussions in February, 1994 and drawn up a Delhi Resolution. This Resolution was endorsed by the SAARC Council of Ministers. It has been adopted in the Eighth SAARC Conference which was held in Delhi. In Dhaka meeting the Ministers in charge of Women and Child Development had some consultations. I had been to Dhaka to attend a meeting held on the 29th and 30th July last. Madam, whatever we have decided in the SAARC meeting is common to all the countries. I have already given a copy of it.

The hon. Member, Shrimati Sushma Swaraj had raised some very important questions. She said that we have omitted some things in our paper. Madam, I would like to inform the hon. Member that the SAARC Resolution is the final one. We cannot change it.

However regarding the country's paper, she can still give some suggestions. We are going to look into those suggestions. She has mentioned about the gender inequality. I would like to say that there may be gender inequality in law. The National Commission on Women has the mandate to review the laws and recommend amendments to various laws which are there in our country. She has also suggested that the Government should call a meeting before the women representatives are sent to Beijing and to decide as to what issues we should project in the meeting. It is a very good suggestion and we will look into it and examine the whole thing and also whether such a meeting can be held before the women are sent to Beijing. I would like to tell the hon. Member that the issues which were common to all women have been included drafted in the country's paper.

Many Members have raised many individual questions which are very much pertinent to our country. The questions which are very much pertinent to our country can be incorporated in our laws

by bringing in some amendments. The National Commission on Women has been constituted to look into various laws. It is looking into various laws like the anti-dowry law and the law against Sati, etc. So many things they have suggested and they are under the consideration of the Government. The moment the Government finalises these suggestions, we will bring them before Parliament for taking necessary action.

Some Members have said that we have not highlighted the empowerment of women and the economic status of women. Poverty is the main question. As far as the SAARC countries are concerned, it is our main concern. We have said very clearly that favourable international economic environment for the SAARC countries including access of market resources and technology on equitable terms, a categorical commitment from the international community of new and additional resources to the strategies and objective identified under the draft platform for action would be an essential preliminary prerequisite. This is very, very important. After we pass the final Resolution, after we come from Beijing, we have to think and discuss as to what action we have to take to implement such a Resolution.

Many Members hare referred to land reforms and wanted to know whether this matter had been discussed in detail. I would like to inform the hon. Members that we have not discussed about land
3.00 P.M.
reforms. We already have laws in regard to violence against women. We are doing our best to curb violence against women. The National Commission for Women is also taking care to investigate cases where the police people have failed and is sending them to the enforcement authorities for necessary action.

In regard to the empowerment, the seven sister countries have met in Delhi and have passed many resolutions. One of the points that they have emphasised is regarding the reservation for women in Legislatures and Parliament. All the parties should discuss this together and come to an understanding. We can only say that reservation for women in legislature and Parliament is possible. As far as reservation for women in grass-roots level is concerned, our country has gone ahead in implementing reservation of one-third of seats for women in the Panchayats and local bodies. That is an area where ten lakh women will get elected. That is one area that we have highlighted before the SAARC and we are going to highlight the same in Beijing also.

Regarding violence against women, there is a chapter in the country's paper. The kind of violence that is taking place has been highlighted there. We have to take action to curb violence.

Our Secretaries had gone to New York very recently. There were some chapters which had been bracketed. We wanted to remove them and see that a common draft is prepared. Only yesterday they have come back from New York

In our country paper we have included the point regarding cultural invasion. We have discussed in detail the role of the media.

Regarding the constitution of the delegation, I think there will be some NGOs and there will also be some experts, some MPs and some officers. Apart from that you have already come to know that a lady MP's delegation is going to Beijing and they will be having a meeting on the 7th.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Are lady Ministers included there or not? I understand some lady Ministers are not going.

SHRIMATI BASAVA RAJESHWARI: That is under the consideration of the Government. I cannot give information unless it is finalised.

SHRIMATI MIRA DAS: I want to ask a simple question. There is a point regarding eradication of poverty. Poverty is caused because of the population explosion. We believe in family planning and family welfare. I would like to know whether the other countries who are represented there also believe in it or not.

SHRIMATI BASAVA RAJESHWARI: They believe in it.

SHRIMATI MIRA DAS: Pakistan does not believe in family planning.

SHRIMATI BASAVA RAJESHWARI: I think many countries believe in it, but we do not want to go into a controversy. Wherever there is unanimity of opinion, we have drafted it. Regarding mainstreaming, empowerment and decision making, mainstreaming of gender perspectives and empowerment of women at all levels in the economic, political and social processes are essential for the uplift of the status of women. I think this will make for empowerment of women. We are going to give an argument to bring women into the mainstream. We have very much emphasised it. It was not there till now.

Regarding protection of the girl child, I think there is already a SAARC Resolution and we have signed it. It urged all the States to take their commitments to the highest level for the elimination of all forms of discrimination against the girl child, which is perpetrated on her throughout her life cycle and evolve appropriate measures, particularly in the field of education, health and nutrition. This would require a similar reaffirmation and commitment from the international community to the special needs of the girl child. Here also, we have highlighted that there should be no discrimination against the girl child. Not only that, but we have also to see that she is protected totally from all kinds of harassments and exposures

We have highlighted the chapter "Violence against Women and Girl Child" also. We have said that the SAARC Member States were in the process of evolving appropriate measures for tackling incidence of violence against women and the girl child including trafficking in women and that these efforts should be further strengthened by evolving legal and institutional frameworks at the national level.

I think, we have highlighted almost all the points which the hon. Members have raised.

An hon. Member asked what action the Government has taken after the Nairobi Conference. Madam, I have got a list of programmes which the Government has taken after we came back from Nairobi. If you want, I will read it out: The ICDS is a major programme. It covers more than 2 crore children and 30 lakh women.

The National Perspective Plan for Women upto 2000AD has been prepared in 1988.

Shram Shakti, the Report of the National Commission on Self-Employed Women and Women in the Informal Sector, 1988.

The National Plan of Action of the SAARC Decade on Girl Child for Survival, Protection and Development of the Girl Child has been drawn up.

Reservation for women in grass-root level democratic institutions.

The National Nutrition Policy has been formulated in 1993.

The National Expert Committee on Women Prisoners, in 1986.

The National Policy on Education, 1986. This Policy aims at universalisation of parimary education and education for all by the end of 2000AD.

Many schemes have been launched for employment and economic development of women like the IRDP, the DWACRA etc.

The National Credit Fund for Women.

The Rashtriya Mahila Kosh was set up for development of women in the informal sector.

The Mahila Samruddhi Yojana was initiated for economic empowerment of women through small savings.

Gender Sensitisation, Programme has been taken up since 1991 through special training packages.

Under the Legal Literacy Programme for Women, ten booklets have been brought out on legal issues concerning women.

Special programmes for development of adolescent girls was launched in 1990.

The National Commission for Women was set up in 1992. A special mechanism for monitoring the programmes for women was set up in 1986.

A National Resource Centre for Women is being set up.

I think, some hon. Members mentioned that in the name of god, girls and women were being exploited. I do agree with him. I have got great concern. My State is one of the States along with the States of Maharashtra and Andhra where young girls are being dedicated as prostitutes in the name of god. We are greatly concerned about it. We have taken up various rehabilitation schemes to see that such girls are separated from their families, to open homes for them and to train them in various skills so that they become good citizens. I have got great concern about that system which is still prevailing in the name of god. These are all local issues. I don't think that we have to highlight them at the inter national level.

As I said before, so many things were bracketted.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): I think you have replied to each and every clarification asked by the hon. Members. I think the Members are satisfied.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Yes.

SHRIMATI SARALA MAHESHWARI: Madam,....

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Do you want to seek some more clarifications?

श्रीमती सरला माहेश्वरी: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदया ने हालांकि बहुत कोशिश की लेकिन मैं अभी भी उस हद तक सहमत नहीं हो पाई हूं क्योंकि मैंने यह प्रश्न जानना चाहा था कि नैरोबी सम्मेलन में जो फारवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी तैयार की गई थी, उस दिशा में हमारे देश द्वारा और तमाम सार्क देशों के द्वारा क्या प्रगति की गई है? मंत्री महोदया ने खासकर हमारे देश के बारे में अभी कुछ योजनाओं के नामों का उल्लेख किया। मैं यह जानना चाहती हूं कि पिछले 4 वर्षों में आपने क्या इस बात का अध्ययन किया है कि महिलाओं की आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक प्रगति कितने स्तर तक हुई है? उसमें प्रगति हुई है या गिरावट आयी है? रोजगार में या उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है या घटी है? संगठित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है या घटी है? मार्किट इकानामी जिसका मैंने उल्लेख किया वह बाजार अर्थव्यवस्था कामकाजी महिलाओं पर और आम तौर पर महिलाओं पर क्या असर डाल रही है, इसकी आपने समीक्षा की तो उसके क्या निष्कर्ष सामने आए? क्या तमाम सार्क देशों ने भी इसकी समीक्षा की? क्या वे अपने प्रगति के कामों से संतुष्ट थे? कृपया करके बताइए कि क्या आपने बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में समीक्षा की और उस समीक्षा के क्या निष्कर्ष उभरकर सामने आए, यह मैं जानना चाहूंगी?

श्रीमती कमला सिन्हा: श्रीमती सरला माहेश्वरी के प्रश्न के साथ जोड़ते हुए मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी।

In all the SAARC countries, some export-processing zones have been established. From my own personal knowledge as a trade union worker, I can tell you, Madam, very emphatically that in these export processing zones women are working in a large number and they are highly exploited. Were these issues discussed in Dhaka or not?

SMT. BASAVA RAJESHWARI: I have already replied. Local issues were not discussed. Those issues which are common....*(Interruptions)*.

SHRIMATI KAMLA SINHA: This is not local issue. Exploitation of women in export-processing zones is not a local issue. It is a SAARC area issue.

SMT. BASAVA RAJESHWARI: We have to discuss that after we come back and the final resolution is adopted. *(Interruptions)*. After they come back, we will dicuss that.

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): सरला जी, मुझे लगता है कि आप लोगों ने जितने भी क्लैरीफिकेशंस ऑनरेबल मिनिस्टर से पूछे हैं, उन सबका जवाब उन्होंने दे दिया है और बार-बार अगर आप उसे रिपीट करके दूसरे ढंग से पूछेगी तो वह ठीक नहीं होगा। She has done very well. No more clarifications now. Now, we shall take up the Statutory Resolution and the Payment of Bonus (Amendment) Bill, 1995.

इसके लिए आलॉटिड टाइम एक घंटा तीस मिनट है। श्री राम जेठमलानी, श्री कृष्णलाल शर्मा, श्री सत्य प्रकाश मालवीय। अच्छा शर्मा जी, आप है। महिलाओं के बीच में आपको भूल ही गई।

श्री कृष्णलाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश): ऐसा होता है, महिलाओं का।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आपका नाम भी तो ऐसा है। भूलना स्वाभाविक ही है।

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) ORDINANCE, 1995

II. THE PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL, 1995

श्री कृष्ण लाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 9 जुलाई 1995 को प्रख्यापित बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 8) का निरनुमोदन करती है।"

महोदया, यह जो बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के संशोधन के लिए एक विधेयक रखा गया है, बोनस संदाय संशोधन विधेयक, 1995, इसके लिए मैंने डिसअप्रूवल के लिए भी रेज़ोल्यूशन मूव किया है और इस विधेयक पर मुझे कुछ अपने विचार भी रखने है। मैं इस विधेयक की भावना के या विधेयक में जो कुछ संशोधन किए गए है, उनके विरोध में नहीं हूं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने डिसअप्रूवल का जो अपना प्रस्ताव रखा है, निरनुमोदन का जो प्रस्ताव रखा है, उसका एक कारण है और वह यह है कि सिद्धांततः क्या यह बात आवश्यक है कि जो विधेयक हम संसद में लाना चाहते हैं, पहले उसको अध्यादेश के रूप में लाएं और फिर उसको यहां पर इस तरह से पेश करें? जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि 9 जुलाई को राष्ट्रपति जी के द्वारा यह अध्यादेश जारी हुआ और इसी महीने में हमारा संसद का सत्र होने वाला था। महोदया, आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि सभापति महोदय सरकार को यह निर्देश दें।

कम से कम कोई मिनिमम गैप एक महीने का या दो महीने का अवश्य रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संसद के सारे अधिकारों का हनन करके इस तरह से हमारे सामने चीजें रख दी जाए और हमें उन पर विचार करना पड़े। यह जो मेरे सामने विधेयक है इसमें यह प्रस्ताव पारित करेंगे कि यह 14 अप्रैल, 1993 से लागू होने वाला है इसके बारे में ऐसी कौन सी अरजेंसी थी कि अगर 20 दिन तक यह अध्यादेश नहीं निकलता तो कौन सा तूफान खड़ा हो जाता, पहाड़ टूट जाता। मैं समझता हूं एक मैटेलिटी, मनोवृत्ति सरकार में काम कर रही है कि हम कोई भी चीज बकायदा सदन में चर्चा करके, विचार-विमर्श करके या सलाह-मशिवरा करके पारित न करें बल्कि उसको अध्यादेश के द्वारा इस तरह से थोपना चाहते है कि सदन के सामने कोई चारा न रह जाए। पहले तो मैं इस पर अपना प्रोटेस्ट करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि चेयरमैन साहब इस बारे में सरकार को निर्देश दें कि अध्यादेश जारी करने की मनोवृत्ति बंद की जाए और कम से कम कोई मिनिमम गैप एक महीने का दो महीने का हो, ऐसा निर्देश होना चाहिए। हमने कभी-कभी देखा है कि सदन शुरू होने कि पन्द्रह दिन पहले बल्कि कई बार तो दो दिन पहले ही अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। इसलिए मैं इस पर अपना डिसअप्रूवल का प्रस्ताव रखता है।